टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप के मोहित जैन आई.एन.एस. के अध्यक्ष बने

वीडियो कॉन्फ्रैस के जरिए आई.एन.एस. का चुनाव आयोजित किया गया था

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। देश के अखबारों मैगज़ीनस और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूज़ पेपर सोसायटी (आई.एम.एस.) की 82वीं महासभा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) व अन्य ऑडियो-विज़ुअल साधनों के जरिए आयोजित की गई थी।

मोहित जैन (इकोनॉमिक टाइम्स) को वर्ष 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़ पेपर सोसायटी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने हैल्थ एण्ड द एन्टीसैप्टिक के एल. आदिमूलम का स्थान लिया है।

वर्ष 2021-22 के लिए के. राजा प्रसाद रेड्डी (साक्षी) राकेश शर्मा (आज समाज) उपाध्यक्ष और तन्मय महेश्वरी (अमर उजाला) सोसायटी के मानद कोषाध्यक्ष होंगे।

मैरी पोल, सोसायटी की महासचिव बनी हैं।

आई.एम.एस. की कार्यकारी कमेटी के अन्य सदस्य हैं:

1.एस. बालसुब्रमण्यम (दैनिक थांथी)
2.गिरीश अग्रवाल (दैनिक भास्कर, भोपाल)
3.समाहित बाल (प्रगतिवादी)
4.गौरव चोपड़ा (फिल्मी दुनिया)
5.विजय कुमार चोपड़ा (पंजाब केसरी, जालंधर)
6.करण राजेन्द्र दर्डा (लोकमल, औरगांबाद)
7.विजय जवाहरलाल दर्डा (लोकमत, नागपुर)
8.जगत सिंह दर्दी (दैनिक यढ़दी कलां)
9.विवेक गोयनका (इंडियन एक्सप्रैस, मुम्बई)
10. महेन्द्र मोहन गुप्ता (दैनिक जागरण)
11. प्रदीप गुप्ता (डेटा क्वेस्ट)
12. संजय गुप्ता (दैनिक जागरण, वाराणसी)
13. शिवेन्द्र गुप्ता (बिज़नैस स्टैण्डर्ड)
14.विवेक गुप्ता (सन्मार्ग)
15. सरविन्दर कौर (अजीत)
16. एम.वी. श्रेयान्स कुमार (मातृभूमि आरोग्य मासिक)

■ राष्ट्रदूत के सोमेश शर्मा आई.एन.एस. कार्यकारिणी में निर्वाचित हुए हैं।

17. डॉ. आर. लक्ष्मीपति (दिनामलार)
18. विलास ए. मराठे (दैनिक हिन्दुस्तान, अमरावती)
19. हर्षा मैथ्यू (वनिता)
20. दिनेश मित्तल (हिन्दुस्तान टाइम्स, पटना)
21. नरेश मोहन (सण्डे स्टेट्समैन)
22. अनन्त नाथ (गृहशोभिका, मराठी)
23. प्रताप जी. पवार (सकला)
24. डी.डी. पुरकायस्थ (सकाल)
25. राहुल राजखेवा (द सैन्टिनल)
26. आर.एम. आर. रमेश (दिनकरन)
27. अतिदेब सरकार (द टेलीग्राफ)
28. प्रवीण सोमेश्वर (द हिन्दुस्तान टाइम्स)

29. किरण डी. ठाकुर (तरूण भारत, बेलगाम)
30. बीजू वर्गीज़ (मंगलम वीकली),
31. आई. वैंकट (अन्नदाता)
32. होर्मुसजी एन. कामा (बॉम्बे समाचार साप्ताहिक)
33. कुन्दन आर. व्यास (व्यापार, मुम्बई)
34. के.एन. तिलक कुमार (डैकन हैराल्ड तथा पुजावाणी)
35. रविन्द्र कुमार (द स्टेट्समैन)
36. किरन बी. वडोदरिया (सम्भाव मैट्रो),
37. पी.वी. चन्द्रन (गृहलक्ष्मी)
38. सोमेश शर्मा (राष्ट्रदूत साप्ताहिक)
39. जयन्त माम्मेन मैथ्यू (मलयाला मनोरमा)
40. शैलेश गुप्ता (मिड डे)
41. एल. आदिमूलम (हैल्थ एण्ड द एन्टीसैप्टिक)

श्रीगंगानगर का 345 टन किन्नू ट्रेन से बांग्लादेश जाएगा

30 दिसम्बर को रवाना होगी ट्रेनः ट्रक में 5 दिन लगते थे, अब 2 दिन लगेंगे

श्रीगंगानगर, 17 दिसम्बर (निसं)। श्रीगंगानगर का किन्नू अब बांग्लादेश में भी अपनी मिठास घोलेगा। एक स्पेशल ट्रेन 30 दिसम्बर को 345 टन किन्नू लेकर श्रीगंगानगर से बांग्लादेश के लिए रवाना होगी।

इसके लिए किन्नू संघ ने रेलवे को इंडैंट सौंप दिया है। विदेश में बेचने के लिहाज से शहर के प्रमुख किन्नू व्यापारी किन्नू की वैक्सिंग, ग्रेडिंग आदि में जुट गए हैं। किन्नू की छंटाई करके इसे डिब्बों में पैक किया जा रहा है।

रेलवे ने 15 रैक की रेल चलाने की अनुमति दी है। किन्नू संघ के अध्यक्ष अरविंद गोदारा, सचिव श्यामलाल बगड़िया और अन्य पदाधिकारियों ने रेलवे को एक लाख रुपए की एडवांस किराया राशि जमा करवाई है। किन्नू संघ में शामिल व्यापारियों ने अपने प्रोडक्शन और जरूरत के हिसाब से ट्रेन में रैक बुक करवाए हैं। श्रीगंगानगर से किन्नू बांग्लादेश भेजने में अब तक पांच दिन तक लगते थे। यह ट्रक से बांग्लादेश सीमा तक पहुंचाया जाता था। इसमें पांच दिन लगते थे, लेकिन अब दो दिन से भी कम समय लगेगा।

किन्नू 40 घंटे में बांग्लादेश बॉर्डर के बनगांव तक पहुंच जाएंगे। बनगांव से आगे इनके ट्रकों में लदान को लेकर भी बात चल रही है। एक ट्रक के लिए 2 लाख रुपए तक किराया लग जाता था। अब किन्नू आधे किराए में ही बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा यानी लागत घटेगी।

■ इस बार जिले में किन्नू का उत्पादन डेढ़ लाख मीट्रिक टन है जो पिछले साल के मुकाबले आधा ही है ऐसे में भाव तो पिछले साल के मुकाबले चार गुणा रहेंगे, लेकिन किन्नू के ताजा रहते विदेश पहुंच जाने से संभावनाएं बढ़ गई हैं तथा अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है।

इस बार जिले में किन्नू का उत्पादन करीब डेढ़ लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल के मुकाबले आधा ही है। ऐसे में भाव तो पिछले साल के मुकाबले चार गुणा रहेंगे, लेकिन किन्नू के ताजा रहते इसके विदेश पहुंचने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और मुनाफा भी अच्छा होने की उम्मीद है। इस बार जिले में दस हजार हैक्टेयर में किन्नू के बाग लगे हैं। इन सभी बाग मालिकों को किन्नू के विदेश में व्यापार और कम लागत में बांग्लादेश तक पहुंचने से लाभ की उम्मीद है। रीको स्थित किन्नू वैक्सिंग प्लांट्स पर हर दिन सैकड़ों क्विंटल किन्नू तैयार किए जा रहे हैं। किन्नू को क्वालिटी वाइज मशीनों से छंटाई करवाकर डिब्बों में पैकेजिंग करवाई जा रही है जहां से इसे बांग्लादेश रवाना किया जाएगा।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सैक्रेट्री सुनील अग्रवाल बताते हैं कि किन्नू के व्यापार में संभावनाओं को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन की अनुमति दी है। ट्रेन 30 तारीख को रवाना होगी। शहर के प्रमुख किन्नू व्यापारी इस संबंध में पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। जैडआरयूसीसी (रेल रोड यात्रि सलाहकार समिति) सदस्य भीम शर्मा के प्रयास से इसमें सफलता मिली। शर्मा ने इस संबंध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के उच्च अधिकारियों के सामने बात रखी थी।

इस पर किन्नू क्लब के अधिकारियों और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ डीआरएम की बैठक हुई। इसमें ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कई मुद्दों पर विचार हुआ।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अवगत करवाने पर उन्होंने तथा स्थानीय सांसद निहालचंद ने विदेश मंत्री से बात की। स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से आखिर ट्रेन को स्वीकृति मिली।

अमेठी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनावी अभियान की शुरुआत जनजागरण पद यात्रा से करेंगे और उसका समापन दोपहर दो बजे एक नुक्कड़ सभा के साथ होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को चेतावनी दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक बैंच ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित द्विक्ससदस्यीय पैगसस जाँच आयोग के कामकाज तथा सभी कार्यवाहियों पर शुक्रवार को "स्टे" लगा दिया।

इस जाँच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर बनाये गये थे। यह "स्टे" दिल्ली के वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर की गई एक पी.आई.एल. पर दिया गया है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी दी, अगर पैगसस प्रकरण की जाँच के लिये गठन कमीशन को भंग नहीं किया।

यह आदेश एक अवमानना-याचिका पर आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 27 अक्टूबर के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य पूर्व जज न्यायमूर्ति आर.वी. रवीन्द्रन की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ-समिति से निगरानी घोटाला (सर्विलेन्स स्कैम) की जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किये गये इस जाँच आयोग में, न्यायमूर्ति लोकुर के अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी एक अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आयोग का गठन कर दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में निगरानी की जाँच की माँग करने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई चल रही थी। ज्ञातव्य है कि यह "निगरानी" इजरायली स्पाई फर्म एन.एस.ओ. के पैगसस सॉफ्टवेयर के जरिये कराई गई थी। भारत के वकीलों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों तथा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की निगरानी के लिये उक्त पैगसस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया जा रहा था।

राजे अब भरतपुर, दौसा में शक्ति प्रदर्शन करेंगी

अमित शाह की नाराजगी के बाद भी वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं

जयपुर, 17 दिसम्बर (का.सं.)। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे पिछले दिनों शोक संवेदना के नाम पर मेवाड़ में यात्रा कर शक्ति प्रदर्शन कर चुकी हैं और वे अब भरतपुर संभाग में शोक संवेदना के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं।

बताया जाता है कि 5 दिसंबर को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक में व जनप्रतिनिधि सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की कड़ी फटकार के बाद भी वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रही हैं।

अमित शाह ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा था कि संगठन से ऊपर कोई नहीं है, संगठन सर्वोपरि है, जो संगठन के साथ चलता है, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता।

अमित शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व व कमल के फूल पर होगा, यानि स्पष्ट है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा।

पिछले दिनों में मेवाड़ में वसुंधरा पार्टी के उन दिवंगत नेताओं को शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची थी जिनका निधन डेढ़ 2 साल पहले करोनाकाल के दौरान हो गया था, अब उसी की तर्ज पर वे भरतपुर और दौसा में कल 18 दिसंबर को लगभग डेढ़ 2 साल पहले और सात 8 महीने पहले दिवंगत हो चुके नेताओं के निवास स्थानों पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा का इतने लंबे समय बाद शोक संवेदना व्यक्त करना तो एक बहाना है, वसुंधरा का असली असली मकसद शोक संवेदना के नाम पर शक्ति प्रदर्शन कर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाना है, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दबाव में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और वह मौजूदा प्रदेश नेतृत्व को मजबूत करने और आगे बढ़ाने का पूरी तरह मन बना चुका है।

वसुंधरा पिछले 2 सालों से प्रदेश में पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं, ज्यादातर मीटिंगों से दूर रहती हैं और पार्टी द्वारा स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद भी उपचुनावों में भी चुनाव प्रचार से दूर रही। वसुंधरा के दौरे को लेकर पूरी कमान पूर्व मंत्री यूनुस खान और पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के हाथ में है, और यह दोनों नेता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर वसुंधरा राजे के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। इनके साथ विधायक कालीचरण सराफ भी भरतपुर दौरे पर हैं जो वसुंधरा राजे के कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। वसुंधरा के मेवाड़ दौरे से लेकर और अब भरतपुर संभाग के दौरे की तैयारियों में यूनुस खान और अशोक परनामी की मुख्य भूमिका सामने आ रही है। मेवाड़ दौरे पर विधायक अशोक लाहोटी भी साथ थे। वहीं वसुंधरा के भरतपुर दौरे को लेकर जो जानकारी मिली है उसमें जिला स्तर पर पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली, कामां से भाजपा के प्रत्याशी रहे जवाहर सिंह बेडम प्रमुख तौर पर सक्रिय होकर स्वागत कार्यक्रमों की तैयारियों में लगे हुए हैं, और लगभग 2 दिन पहले प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा इन सभी नेताओं से भरतपुर में गुप्त बैठकें कर वसुंधरा राजे के कार्यक्रमों की रूपरेखा में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन यह जानकारी भी मिल रही है कि भजनलाल शर्मा वसुंधरा के कार्यक्रमों से तो दूर रहेंगे लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी भूमिका निभा रहे हैं। संगठन की नजरों में वे पाक साफ बनने की कई बार कोशिश कर चुके हैं।

■ शोक संवेदना व्यक्त करने के नाम पर राजे इन दिनों राजस्थान में जगह-जगह शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं।

■ हाल ही में उन्होंने मेवाड़ अंचल में भी शक्ति प्रदर्शन किया था।

सूत्रों की माने तो पिछले साल 8 मार्च को वसुंधरा राजे के भरतपुर में जन्मदिन की तैयारियों में कई दिन पहले भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रमों की रूपरेखा में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन जन्मदिन से एन वक्त पर पश्चिम बंगाल चुनावों में चले गए थे।

यूनुस खान, अशोक परनामी, रामस्वरूप कोली, बहादुर सिंह कोली इत्यादि पिछले कई दिनों से भरतपुर जिले में मंडल और बूथ के पदाधिकारियों पर भी वसुंधरा के स्वागत कार्यक्रम में आने का भी दबाव बना रहे हैं। यूनुस खान और अशोक परनामी दौसा जिले में भी वसुंधरा के स्वागत कार्यक्रम में आने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, इसमें दौसा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी की भूमिका भी पर्दे के पीछे से सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वसुंधरा को मेवाड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिखित में कड़ी फटकार मिल चुकी है, अब भरतपुर और दौसा के शक्ति प्रदर्शनों को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह नजर जमाए हुए है।

भूटान ने भी मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया

प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला भूटान नवां देश है

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान, अमेरिका और सऊदी अरब सहित नौ देश सर्वोच्च नागरिक अलंकरण से विभूषित कर चुके हैं। भूटान नौवां देश है जिसने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण 'नगदग पेल जी खोरलो' से सम्मानित करने की घोषणा की है। इससे पहले मोदी को आठ देश तथा पांच अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने सर्वोच्च अलंकरणों से सम्मानित कर चुके हैं। मोदी को सबसे पहले सऊदी अरब ने 2016 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बादशाह अब्दुल अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान ने 2016 में ही 'अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान' से नवाजा। मोदी को फिलिस्तीन ने 2018 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर आफ द स्टेट आफ फ़िलिस्तीन' से विभूषित किया। उसके अगले साल संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक खिताब 'आर्डर ऑफ जायद' सम्मान से नवाजा। मोदी को रूस ने 2019 में ही 'सेंट एंड्रयू' सम्मान और मालदीव ने 'रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन' तथा बहरीन ने 'ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां' सम्मान से विभूषित किया।

■ भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 'नगदग पेल जी खोरलो' से सम्मानित करने की घोषणा की।

बांग्लादेश में पुनरूद्धारित काली मंदिर जनता को समर्पित

ढाका 17 दिसम्बर (वार्ता)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन यहां रमना काली मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार हिस्से का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति कोविंद के साथ केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार भी थे। रमना काली मंदिर समिति के अध्यक्ष उत्पल सरकार ने कहा कोविंद ने राजधानी ढाका में सबसे पुराने मंदिर को दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद मंदिर में 15 मिनट तक रहे, जहां उन्होंने भारत सरकार के अनुदान से मंदिर के जीर्णोद्धार हिस्से का उद्घाटन किया। बाद में मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि 27 मार्च 1971 में यहां इस स्थान पर नरसंहार हुआ था। रमना मंदिर को पाकिस्तानी अत्याचारियों ने नष्ट किया था। भारत सरकार की ओर से सात करोड़ रुपये के अनुदान से मंदिर के हिस्से का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर और मुख्य मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया गया है।

राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह और मुजीब वर्ष के समापन समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पत्नी और पुत्री के साथ तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर बुधवार सुबह ढाका पहुंचे। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को पहले दिन हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सावर में राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। सावर से लौटकर उन्होंने धनमंडी नंबर 32 पर बंगबंधु की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की और स्मारक संग्रहालय का दौरा किया। कल सुबह राष्ट्रपति कोविंद ने शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित नेशनल परेड ग्राउंड में विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया था। उन्होंने दोपहर में जातीय संघ के साउथ प्लाजा में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु के जन्म शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लिया।

■ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन रमना काली मंदिर के जीर्णोद्धार हिस्से का उद्घाटन किया।

स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को 'सामान्य' श्रेणी में तब्दील करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने आरक्षण के लिए जरूरी प्रक्रियाओं यानी तीन स्तरों पर परीक्षण किये बिना ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को कानून के खिलाफ बताते हुए रोक लगायी। शीर्ष न्यायालय ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की तब्दील करने लिए राज्य चुनाव आयोग पुनः अधिसूचना जारी और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाये। अदालत ने स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटों के आरक्षण के मद्देनजर मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी चार दिसंबर, 2021 की चुनाव अधिसूचना पर रोक की एक याचिका पर सुनवायी के बाद यह आदेश दिया। पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को संविधान के मुताबिक ग्राम पंचायत एवं नगर निगमों के चुनाव कराने का दिया।

एमेज़ॉन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली,17 दिसंबर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि. में हिस्सेदारी खरीदने के लिए ई-वाणिज्य क्षेत्र की कंपनी एमेज़ॉन के सौदे को दो वर्ष पहले दी गई मंजूरी को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। आयोग ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण एमेज़ॉन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। एमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच घरेलू कंपनी ने प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष ई-वाणिज्य कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। दरअसल फ्यूचर समूह के रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) के साथ प्रस्तावित 24,713 करोड़ रूपये के समझौते के बाद दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई और इसी की पृष्ठभूमि में फ्यूचर समूह ने सीसीआई के समक्ष शिकायत की थी। आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि उक्त मंजूरी "कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी। कुछ उल्लंघनों का हवाला देते हुए सीसीआई ने कहा कि इनके पीछे एमेज़ॉन द्वारा समझौते के उद्देश्य और इसकी वास्तविक क्षमता को दबाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास थे। इसके साथ ही आयोग ने अमेजन पर दो करोड़ रूपये का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा सौदे की आवश्यक शर्तों के बारे में जानकारी देने में विफल रहने पर अतिरिक्त 200 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। एमेज़ॉन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश की हम विवेचना कर रहे हैं और इसके बाद आगे के कदमों के बारे में कोई निर्णय लेंगे। सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एमेज़ॉन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी। नवंबर 2019 में सौदे को मंजूरी देते हुए सीसीआई ने यह भी कहा था कि अधिग्रहणकर्ता द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो आदेश को रद्द मान लिया जाएगा।

■ सी.सी.आई. ने एमेज़ॉन के सौदे को निलंबित कर करोड़ों का जुर्माना लगाया।

उच्चतम न्यायालय ने 29 नवंबर को एमेज़ॉन को सीसीआई के समक्ष पेश होकर अपनी दलीलें रखने के लिए दो सप्ताह का वक्त और दे दिया था।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ निवेश सौदे के लिए अमेजन को दी गई मंजूरी वापस लेने से संबंधित मामले में सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया था। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच फ्यूचर रिटेल की संभावित बिक्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।

रिलायंस रिटेल के हाथों फ्यूचर रिटेल के 24,713 करोड़ रुपये के अधिग्रहण सौदे का अमेजन यह कहते हुए विरोध कर रही है।

'भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह तीन महीने के अन्दर उस याचिका पर अपना निर्णय दे, जिसमें केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित, भाजपा के उन चार नेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की अनुमति मांगी है, जिनके कथित नफरत भरे भाषणों (हेट स्पीच) के फलस्वरुप दिल्ली में 2020 के दंगे हुये थे। तीन अन्य नेता हैं- भाजपा सांसद कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा तथा अभय वर्मा। यह याचिका उस हिंसा के शिकार हुये तीन लोगों ने दायर की है, जिस हिंसा ने गत वर्ष राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों को निगल लिया था। इन तीन लोगों ने इन भाजपा नेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने, तथा उनके कथित घृणा एवं द्वेष भरे भाषणों की जांच के लिये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित किये जाने की मांग की है। न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव तथा भूषण आर. गवई की बैंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह इस प्रकरण की सुनवाई जल्दी ही, तीन महीनों के अंदर ही करे। हिंसा-पीड़ितों का कहना था कि उच्च न्यायालय "कार्यवाही में विलम्ब" कर रहा है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिये तीन माह का समय दिया दिल्ली हाई कोर्ट को।

कोवोवैक्स को डब्ल्यु.एच.ओ. की मंजूरी

नई दिल्ली 17 दिसंबर (वार्ता)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यु.एच.ओ.) ने कोविड के मरीजों के इलाज के लिये भारत में निर्मित एक और टीके 'कोवोवैक्स' को मंजूरी दी है।

डब्ल्यु.एच.ओ. ने इससे पहले भारत में निर्मित दो कोविड टीके कोविशील्ड और कोवैक्सिन को कोविड इलाज में प्रयोग करने की मंजूरी दी है। डब्ल्यु.एच.ओ. ने शुक्रवार को बताया कि पुणे के सीरम इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोवोवैक्स के आपात प्रयोग की मंजूरी दी।

राजघराने में आपसी समझौते के बाद जयमहल पैलेस देवराज...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लड़ी। लम्बी कानूनी लड़ाई में न्यायालयों के अधिकांश निर्णय देवराज सिंह और लालित्य कुमारी के पक्ष में गए।

देवराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जयमहल पैलेस के मालिकाना हक के मामले में स्वर्गीय पृथ्वीराज, जयसिंह और पृथ्वीराज के एकमात्र पुत्र विजित सिंह पर दावा ठोक रखा था। देवराज और लालित्य कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे में कहा था कि 1997 में जगत सिंह के निधन के बाद जयसिंह, पृथ्वीराज और उनके पुत्र ने गलत तरीके से जयमहल पर कब्जा कर रखा है।

उन्होंने दावा किया कि जयमहल का स्वामित्व सिर्फ उनके पिता जगतसिंह के पास था, जिसे उन्होंने एक कंपनी बनाकर होटल में परिवर्तित कर दिया था। होटल की हिस्सेदारी में अधिकांश शेयर जगतसिंह के पास थे। बहुत ही मामूली शेयर संचालक के रूप में पृथ्वीराज को दे रखे थे। लेकिन पृथ्वीरराज ने समय-समय पर अपने शेयर में गलत ढंग से वृद्धि कर ली।

जगत सिंह के निधन के बाद कानूनी लड़ाई में पुत्र और पुत्री ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए पैतृक सम्पत्ति में अपनी हिस्सेदारी माँगी।

लम्बी कानूनी लड़ाई जिला स्तर के न्यायालय से लेकर कंपनी लॉ बोर्ड और उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। अन्ततः सुप्रीम कोर्ट ने राजपरिवार के सदस्यों को सलाह दी कि इस पूरे जटिल मामले को आपसी समझौते से निपटा ले तो श्रेयस्कर होगा। इसके बाद सभी पक्षों ने इस विषय पर गहन मन्त्रणा कर समझौते को स्वीकृति दी और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ को मध्यस्थ बनाया। पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ के सतत प्रयासों के बाद सभी पक्षों ने पूरे मसले का हल निकालने के लिए बैठकें की।

इसके बाद 15 दिसम्बर, 2021 को देवराज सिंह और लालित्य कुमारी के सौतेले ताऊ जयसिंह तथा स्वर्गीय पृथ्वीराज के पुत्र विजित सिंह ने जयमहल पैलेस को पूर्व न्यायाधीश जोसफ के समक्ष सौंपने की स्वीकृति दे दी।

इस समझौते पर सभी पक्षों के हस्ताक्षरों के बाद पूर्व न्यायाधीश जोसफ ने अपनी रिपोर्ट और टिप्पणी के साथ दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर जयमहल पैलेस का स्वामित्व देवराज सिंह और लालित्य कुमारी को सौंपने के आदेश जारी किए।

देवराज सिंह और लालित्य कुमारी की ओर से दिल्ली की एक विधि परामर्शदाता कंपनी प्राइम लीगल इंडिया एल.एल.पी. के अभिषेक कुमार राव वकील थे। जयसिंह, पृथ्वीराज और विजित सिंह की ओर से संजीब सेन ने पैरवी की।

वकील अभिषेक राव ने कहा कि इतने लम्बे से चल रहा कानूनी मसला आपसी सद्भाव और विश्वास के कारण सुलट गया। लेकिन इस विवाद से निपटारे के लिए पूर्व न्यायाधीश जोसफ की विद्वता और उनके प्रति सभी के विश्वास को सर्वाधिक श्रेय जाता है।

अभिषेक राव ने स्वर्गीय जगत सिंह की पूर्व पत्नी प्रियनन्दना द्वारा अपनी संतानों को उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार दिलाने के लिए किए गए संघर्ष की प्रशंसा की।

समझौते के दौरान जब हस्ताक्षर हुए उस समय पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ, जयसिंह, देवराज सिंह, जयसिंह के पुत्र अजय सिंह, पृथ्वीराज के पुत्र विजित सिंह और ठाकुर हरीसिंह और ठाकुर प्रताप सिंह मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मूल प्रति प्राप्त होने के बाद दोनों पक्ष जयमहल पैलेस की सम्पत्ति संबंधी कार्य हाथ में लेंगे। समझौते में कई शर्तों के बाद इसकी सूचना जयमहल पैलेस का संचालन कर रही टाटा की इण्डियन होटल्स लिमिटेड को दी जाएगी।

आरम्भ से ही मैनेजमैन्ट कांट्रेक्ट के तहत टाटा की कंपनी जयमहल पैलेस का संचालन कर रही है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600